

तरजीही आवंटन से जुटाई गई रकम पांच साल के उच्चस्तर पर

दीपक कोरगांवकर और
पुनीत वाधवा
मुंबई/नई दिल्ली, 22 दिसंबर

कंपनियों की तरफ से तरजीही आवंटन के जरिए जुटाई गई रकम पांच साल के उच्चस्तर पर पहुंच गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ भारतीय कंपनी जगत ने प्रवर्तकों व शेयरधारकों को तरजीही आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित कर कैलेंडर वर्ष 2015 के पहले 11 महीने में 45,209 करोड़ रुपये जुटाए।

कैलेंडर वर्ष 2014 में कंपनियों ने तरजीही आवंटन के जरिए 29,212 करोड़ रुपये जुटाए थे जबकि कैलेंडर वर्ष 2013 में 44,836 करोड़ रुपये, कैलेंडर वर्ष 2012 में 38,276 करोड़ रुपये और कैलेंडर वर्ष 2011 में 27,161 करोड़ रुपये जुटाए। यह जानकारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों से मिली।

मौजूदा कैलेंडर वर्ष में हुई बढ़ोतरी सरकार की तरफ से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उपलब्ध कराई गई पृष्ठभूमि में हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 17 बैंकों ने इस कैलेंडर वर्ष में तरजीही शेयर के जरिए जुटाई गई कुल रकम का 68 फीसदी यानी 30,822 करोड़ रुपये जुटाए। साल 2014 में आंकड़े बताते हैं कि

महीना	दृश्य की संख्या	रकम (करोड़ रुपये में)
जनवरी 2015	12	2141
फरवरी 2015	18	936
मार्च 2015	11	1171
अप्रैल 2015	25	10436
मई 2015	23	5329
जून 2015	19	1399
जुलाई 2015	11	474
अगस्त 2015	8	1701
सितंबर 2015	15	881
अक्टूबर 2015	16	15962
नवंबर 2015	20	4780

स्रोत : एनएसई

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने तरजीही आवंटन के जरिए 18,617 करोड़ रुपये जुटाए थे। इक्विनामिक्स रिसर्च एंड एडवाइजरी के संस्थापक व प्रबंध निदेशक जी चोकरासिंगम ने कहा, पीएसयू बैंकों की तरफ से तरजीही आवंटन की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिला है। एक बार फिर यह मुख्य रूप से बढ़ते एनपीए के चलते पूंजी पर्याप्तता के मामले में उन पर पड़े दबाव का नतीजा है।

आंकड़ों से पता चलता है कि सुजलान एनर्जी, रिलायंस कम्युनिकेशंस, प्राइम फोकस, जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी और मैग्मा फिनकोर्प निजी क्षेत्र की उन कंपनियों में शामिल हैं जिन्होंने तरजीही शेयर के जरिए 500 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए।

बैंकों की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक ने 8363 करोड़ रुपये

जुटाए जबकि बैंक ऑफ इंडिया ने 3097 करोड़ रुपये। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ोदा ने 3046 करोड़ रुपये, केनरा बैंक ने 3037 करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक ने 2602 करोड़ रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2243 करोड़ रुपये और इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2009 करोड़ रुपये जुटाए।

के आर चोकसी रोयर्स एंड सिविलिटोज के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यवाहिकारी देवेन चोकसी ने कहा, एक अवधि में बैंकों के खजाने में करीब 70,000 करोड़ रुपये आएंगे। सरकारी रकम से पीएसयू बैंकों का पुनर्पूँजीकरण हो रहा है। नियम के तहत पीएसयू बैंकों को अगले तीन-चार सालों में पूँजीकृत होने के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये की दरकार होगी। ऐसे में स्पष्ट तौर पर पहले दौर की फंडिंग सरकार की तरफ से होगी और इसके बाद उच्च कोमत पर वैश्विक निवेशकों को हिस्सेदारी के विनिवेश के जरिए ऐसा होगा।

सरकार की तरफ से पीएसयू बैंकों को पूँजी दिए जाने के बाद भी विश्लेषक चिंतित हैं। विश्लेषकों ने कहा, सरकारी बैंकों का द्रुवत ऋण सितंबर तिमाही में बढ़ा है क्योंकि पहले आसानी से पुनर्भूगतान करने वाले कुछ देनदार व्याज चुकाने में नाकाम रहे हैं।